दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 24 सितंबर, 2013
निर्णीत : 16 दिसंबर, 2013

आप.अ.115/2000

गोपी उर्फ़ हुकम ..... अपीलार्थी

द्वारा : श्री सुशांत सिंह, अधिवक्ता के साथ श्री पी.सी. आर्य और श्री तेजिंदर सिंह, अधिवक्तागण।

बनाम

राज्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री एम.एन. डुडेजा, अति.लो.अभि.।

और

आप.अ.73/2000

शांति देवी ..... अपीलार्थी

द्वारा : श्री सुशांत सिंह, अधिवक्ता के साथ श्री पी.सी. आर्य और श्री तेजिंदर सिंह, अधिवक्तागण।

बनाम

राज्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री एम.एन. डुडेजा, अति.लो.अभि.।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी.गर्ग

<u>एस.पी.गर्ग, न्या.</u>

1. गोपी उर्फ़ हुकुम (अपीलार्थी-1) और शांति देवी (अपीलार्थी-2) ने प्राथमिकी संख्या 978/97 थाना मंगोलपुरी से उत्पन्न सत्र मामला संख्या 2/98 में विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश के दिनांक 17.07.1999 के फैसले की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाया, जिसके द्वारा उन्हें भा.दं.सं. की धारा 34 सहपठित भा.दं.सं. की धारा 498क/304ख के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था और भा.दं.सं. की धारा 304ख के तहत प्रत्येक को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। आरोप-पत्र में पेश किए गए तथ्य इस प्रकार हैं :

2. हेमलता, अभि.सा.-1 (बाबू लाल) की बेटी की शादी अपीलार्थी-1 से 17.05.1997 को हुई थी। उसके माता-पिता द्वारा उसे उनकी आर्थिक क्षमता के अनुसार विभिन्न दहेज के सामान दिए गए थे। शादी के बाद, हेमलता अपने वैवाहिक घर (ससुराल) यानी घर सं. आई-735, मंगोलपुरी में रहती थी। अभियोजन पक्ष का मामला है कि शादी के बाद उसे दहेज की मांग के संबंध में अपने पति और उसकी मां के हाथों उत्पीड़न और क्रूरता को झेलना पड़ा था। जब वह अपने साथ हुए उत्पीड़न और क्रूरता को सहन करने में असमर्थ हो गई, तो 05.10.1997 को पूर्वाह्न लगभग 1 बजे उसने खुद पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा ली। उसके शरीर पर 95%-98% जलने के घाव थें और उसके पति अपीलार्थी-1 द्वारा उसे ई.एस.आई. अस्पताल, नई दिल्ली ले जाया

गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद दैनिक डायरी (डीडी) संख्या 43बी (प्र.अभि.सा.-10/ए) को पुलिस थाना मंगोलपुरी में 5.10.1997 को अपराह्न 03.25 बजे पर दर्ज किया गया था और जांच उप.नि. प्रकाश चंद को सौंपी गई थी, जो कांस्टेबल राजा राम के साथ अस्पताल गए और हेमलता के चिकित्सा विधिक मामला (प्र.अभि.सा.-2/ए) को एकत्र किया। चूंकि वह बयान देने के लिए शारीरिक रूप से असमर्थ थी, इसलिए जांच अधिकारी ने अभि.सा.-6 (आर.एल. शर्मा, उपखंड मजिस्ट्रेट) को सूचित किया और उसने 06.10.1997 को अपराह्न 03.30 बजे उसका बयान (प्र.अभि.सा.6/ए) दर्ज करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। हेमलता ने अस्पताल में 06.10.1997 को दम तोड़ दी। चूंकि यह अप्राकृतिक मृत्यु का मामला था, इसलिए 07.10.1997 को शव परीक्षण किया गया और अभि.सा.3 (डॉ. बी.एन. आचार्य) की राय में, मृत्यु का कारण 98% मृत्यु-पूर्व जलना और घाव का सड़ना था। जाँच के दौरान, तथ्यों से परिचित गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; विचारण के लिए भेजा गया; विधिवत आरोप लगाया गया और विचारण में लिया गया। अभियोजन पक्ष ने अपने अपराध को स्थापित करने के लिए दस गवाहों से पूछताछ की। अपने 313 बयानों में, उन्होंने झूठे आरोप लगाने का अभिवाक किया और अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि हेमलता के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया गया और उसकी आत्महत्या करने का कारण उसकी लाइलाज बीमारी थी। वह अपनी शादी से नाखुश थी जो उसे पसंद नहीं थी। प्र.सा.-1 (दर्शन लाल), प्र.सा.-2 (माया) और

प्र.सा.-3 (रामबीर) बचाव में पेश हुए। विचारण न्यायालय, साक्ष्य विशेष रूप से मृत्युकालिक कथन और पक्षकारगण की विरोधी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि दोनों अपीलार्थी उसकी दहेज मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। दोषसिद्धि और सजा के आदेशों से व्यथित होने के कारण उन्होंने अपील की है।

3. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख की जाँच की। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय अपने सही परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य को समझने में विफल रहा और बिना वैध कारणों के अभि.सा.-1, 5, 7, 8 और 9 के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभासों को नजरअंदाज कर दिया। शादी के समय दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी और दहेज की मांग के संबंध में उत्पीड़न या क्रूरता के आरोप दुखद मृत्यु के बाद ही सामने आए। घटना से पहले, किसी को भी अपीलार्थीगण के आचरण और व्यवहार के बारे में कोई शिकायत नहीं थी। न तो मृतका और न ही उसके माता-पिता ने कभी भी मृतका को शारीरिक या मानसिक यातना देने के लिए किसी भी प्राधिकारी के पास कोई शिकायत दर्ज कराई। दंपत्ति गृह (ससुराल) में रह रही मृतका की बहन रेखा ने अपने माता-पिता या किसी रिश्तेदार को उसके साथ हुई क्रूरता के बारे में सूचित नहीं किया। भा.दं.सं. की धारा 304ख/498क के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता है क्योंकि यह स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कोई ठोस और सार्थक सबूत

नहीं था कि 'मृत्यु से कुछ समय पहले', हेमलता को दहेज की मांगों को पूरा न करने के कारण प्रताड़ित किया गया था। विचारण न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन पर मृतका के अंगूठे की छाप प्राप्त करने के संबंध में अभि.सा.-2 (डॉ. आर.के.शर्मा) और अभि.सा.-6 (आर.एल.शर्मा, एस.डी.एम.) के बयानों में महत्वपूर्ण विसंगतियों को महत्व नहीं दिया। यह वास्तव में क्या हुआ था, इसका कोई सच्चा विवरण इसमें नहीं है। यह घटना के अगले दिन दर्ज किया गया था और उसके माता-पिता द्वारा उसे सिखाने-पढ़ाने की पूरी संभावना थी। आत्महत्या करने का वास्तविक और तात्कालिक कारण यह था कि हेमलता लाइलाज बीमारी के कारण खड़े होने या चलने में असमर्थ थी, जिसके लिए वह नियमित चिकित्सा उपचार ले रही थी। चूंकि, शादी से पहले उसके पड़ोस के एक लड़के के साथ संबंध थे और उसे अपीलार्थी-1 से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए वह दंपत्ति गृह (ससुराल) में रहने से खुश नहीं थी। वह अपनी बीमारी के कारण निराश और हताश थी। इसके विपरीत, राज्य की तरफ से विद्वान लोक अभियोजक ने अपील का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि 26 वर्षीय लड़की हेमलता की शादी के छह महीने के भीतर उसकी ससुराल में मृत्यु हो गई। अपीलार्थीगण ने उसकी स्वामिभक्ति पर संदेह करते हुए आरोप लगाया कि उसने एक पड़ोसी के साथ संबंध बना लिए थे और उससे शादी करना चाहती थी। एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा दर्ज की गई मृत्युकालिक कथन स्पष्ट रूप से उसकी मौत के लिए उसे ही दोषी ठहराया

गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य गवाहों से पूछने पर बिना किसी बड़े बदलाव के उसके बयान की पुष्टि की है।

4. यह स्वीकार किया गया है कि हेमलता की अपीलार्थी-1 के साथ शादी के छह महीने के भीतर उसकी ससुराल में मृत्यु हो गई थी। यह भी निर्विवाद है कि उनकी मृत्यु आत्महत्या का मामला था और यह उन्हें जलने से हुई 95%-98% घाव के कारण हुई थी। जब हेमलता ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर अपने जीवन का अंत किया, तब दोनों अपीलार्थी मौजूद थे। उन्हें नई दिल्ली के ई.एस.आई. अस्पताल में अपीलार्थी-1 और चिकित्सा विधिक मामला (प्र.अभि.सा.2/ए) द्वारा ले जाया गया था, जहाँ रोगी के आने का समय अपराह्न 03.45 दर्ज किया गया है। कथित विवरण अभिलेख में लिखा है कि हेमलता ने 'पति के साथ हुए झगड़े के कारण खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को जला लिया था'। यह बयान हेमलता ने अभि.सा.-2 (डॉ.आर.के.शर्मा) को दिया था, जिन्होंने उनके पति (अपीलार्थी-1) की उपस्थिति में उसकी चिकित्सकीय जांच की थी। वह उस समय होश में थी। अपीलार्थी-1 ने उसका खंडन नहीं किया और अभि.सा.-2 (डॉ.आर.के.शर्मा) को किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया जिससे हेमलता को खुद को आग लगाने के लिए अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। जाहिरा तौर पर अपीलार्थी-1 ने घटना से कुछ समय पहले मृतका के साथ झगड़ा किया था और

उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया था। अपीलार्थीगण ने घटना के दिन हुए झगड़े का कोई उचित कारण नहीं बताया।

5. अभि.सा.-6 (आर.एल.शर्मा, एस.डी.एम.) ने हेमलता को बयान के लिए उपयुक्त घोषित किए जाने के बाद 06.10.1997 को अपराह्न 03.30 बजे मृत्युकालिक कथन (प्र.अभि.सा.-6/ए) दर्ज किया। चिकित्सा विधिक मामला (प्र.अभि.सा.-2/ए) रिकॉर्ड किया कि जब हेमलता को 05.10.1997 को ई.एस.आई. अस्पताल लाया गया तो वह होश में थी और उसने खुद की जांच करने वाले डॉक्टर का अभिकथित इतिवृत्त बताया था। अभि.सा.-6 ने अपने अदालती बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि जब वह संतुष्ट हो गयी कि हेमलता होश में है और बयान देने के लिए स्वस्थ मानसिक और शारीरिक स्थिति में है, उसने इसे प्रश्नोत्तर के रूप में दर्ज किया, उससे उसका नाम, पति का नाम, शादी की तारीख और घटना के कारण के बारे में सवाल किया। उन्होंने सभी प्रश्नों का स्वतंत्र रूप से, स्वेच्छा से और सुसंगत रूप से उत्तर दिया। उसने आगे कहा कि हेमलता ने खुलासा किया कि उसका पति और सास उसे परेशान करते थे और इस वजह से उसने खुद को जलाने का कदम उठाया। उसने विशेष रूप से कहा कि उसकी सास उसे बुरी तरह से परेशान करती थी और उसे उसके पति के साथ-साथ विधि के अनुसार बरता जाना चाहिए। बयान पढ़ा गया और उसके बाएं अंगूठे का निशान प्र.अभि.सा.-6/ए पर बिंदु 'ए' पर लिया गया। प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने कहा कि बयान दर्ज करने में देरी पीड़ित की शारीरिक

और मानसिक स्थिति के कारण 05.10.1997 को बयान देने में असमर्थता के कारण थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मृत्युकालिक कथन (प्र.अभि.सा.-6/ए) मनगढ़ंत थी और इसमें बिंदु 'ए' पर उसके अंगूठे का निशान नहीं था। वर्तमान मामले में, उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युकालिक कथन प्रश्नोत्तरी के रूप में और यथासाध्य, उसके शब्दों में दर्ज की गई थी। जब मृत्युकालिक कथन को सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा कथनकर्ता के शब्दों में दर्ज किया जाता है, तो यह बहुत उच्च स्तर पर होता है और इसका साक्ष्य मूल्य अधिक होता है। सक्षम मजिस्ट्रेट के पास पीड़ित की मृत्युकालिक कथन में नामित व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और परिस्थितियों के आभाव में कुछ भी विपरीत दिखाने पर, उस पर न्यायालय द्वारा अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए। अभि.सा.-6 (आर.एल.शर्मा, एस.डी.एम.) के उच्च पद पर स्वतंत्र गवाह होने के कारण ऐसा कुछ भी करने का कोई कारण नहीं था, जो उचित न हो। इस प्रकार, उनके द्वारा दर्ज की गई मृत्युकालिक कथन की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। आम तौर पर, न्यायालय यह संतुष्ट करने के लिए कि क्या मृतका मृत्युकालिक कथन के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति में था, चिकित्सकीय राय लेती है। अभि.सा.-2 (डॉ.आर.के.शर्मा) ने अभिसाक्ष्य दिया कि 06.10.1997 को अपराह्न लगभग 03.30 बजे रोगी की जांच करने के बाद, उन्होंने पृष्ठांकन (प्र.अभि.सा.-2/बी) के जरिए उसे बयान देने के लिए स्वस्थ घोषित किया था। बयान दर्ज करने से पहले, अभि.सा.-6 ने मृतका की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुद को संतुष्ट किया था। गवाह को कोई सुझाव

नहीं दिया गया कि वह अपने माता-पिता और परिवार के सदस्यों के प्रभाव में थी और उसे ऐसा करने के लिए सिखाया गया था। यह अनुमान लगाने के लिए कोई परिस्थिति अभिलेख पर नहीं लाई गई है कि कथन सिखाए जाने, संकेत देने या कल्पना का परिणाम थी। यह सच है कि अभि.सा.-2 (डॉ.आर.के.शर्मा) और अभि.सा.-6 (आर.एल.शर्मा, एस.डी.एम.) ने अंगूठे/पैर के अंगूठे के निशान प्राप्त करने के बारे में विरोधाभासी बयान दिया है। डॉक्टर ने अपने समझदारी से 05.10.1997 को चिकित्सा विधिक मामला (प्र.अभि.सा.-2/ए) पर पीड़िता के पैर के अंगूठे का निशान लिया क्योंकि उसके अंगूठे जल गए थे। अगले दिन दर्ज की गई मृत्युकालिक कथन (प्र.अभि.सा.-6/ए) में प्र.अभि.सा.-6/ए पर बिंदु 'ए' पर उसके अंगूठे का निशान है। यह विसंगति एक सक्षम अधिकारी द्वारा दर्ज की गई मृत्युकालिक कथन की सत्यता और वास्तविकता पर संदेह करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मृत्युकालिक कथन में, हेमलता ने लगातार दोनों अपीलार्थीगण पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। उसने खुलासा किया कि अपीलार्थीगण पिछले तीन दिनों से उसके साथ झगड़ा कर रहे थे। घटना के दिन भी उनका उससे झगड़ा हुआ था। उसने खुलासा किया कि उसके माता-पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज के सामान दिए थे और उनके द्वारा दहेज के लिए उसे परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा था। मृत्युकालिक कथन में, उसने निश्चित कारण बताया कि उसे आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर किया गया, अर्थात उनके द्वारा किया गया उत्पीड़न। उसने अपीलार्थीगण को उपयुक्त सजा देने की अपील की; विशेष रूप से उसकी

सास जो उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करती थी। अपीलार्थीगण ने इस बारे में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया कि हेमलता ने उन्हें क्यों फंसाया और किस बात ने एक नवविवाहित पत्नी को अपनी शादी के छह महीने के भीतर आख़िरी कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। मृतका को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाली आसपास की परिस्थितियाँ उनकी विशेष जानकारी में थीं और साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत, यह खुलासा करना और साबित करना उनका आवश्यक कर्तव्य था क्योंकि घटना दंपत्ति गृह (ससुराल) में हुई थी। उन्होंने असंगत और अलग-अलग बचाव प्रस्तुत किया कि उसका शादी से पहले ही पड़ोस के एक लड़के के साथ संबंध था और वह उससे शादी करना चाहती थी। हालाँकि, विचारण के दौरान उक्त लड़के का नाम कभी सामने नहीं आया। उसके पिता को एक और सुझाव दिया गया कि उसकी (हेमलता) शादी से पहले से ही चरित्र अच्छा नहीं थी या अपीलार्थी-1 के साथ उसकी शादी उसकी इच्छा के खिलाफ हुई थी। यह भी सुझाव दिया गया था कि वह अक्सर पड़ोसी को फोन करती थी, जिस पर अपीलार्थीगण ने आपत्ति जताई थी। एक अन्य कारण यह बताया गया कि मृतका एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित था और उसी कारण उसने आत्महत्या कर ली। यह बात अभिलेख पर आया है कि हेमलता किसी यौन रोग से पीड़ित थीं और चलने और खड़े होने में असमर्थ थीं। अभि.सा.-9 (रेखा) उसकी सहायता के लिए ससुराल में रहने आई थी। हालाँकि, यह स्थापित नहीं किया गया है कि उसे नियमित उपचार दिए जाने के बावजूद बीमारी लाइलाज थी। अपीलार्थीगण ने बीमारी की स्थिति/फैलाव का आकलन करने और

यह पता लगाने के लिए कि क्या यह उपचार योग्य नहीं है, कोई भी चिकित्सा दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने यह नहीं बताया कि कौन सी तात्कालिक मजबूर करने वाली परिस्थिति थी जिसने उस दिन मृतका को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने धारा 313 के तहत जाँच में उनसे पूछे गए सभी प्रश्नों को अस्वीकार कर दिया और किसी भी प्रश्न का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने झूठा बचाव करते हुए कहा कि हेमलता की शादी से पहले एक लड़के के साथ अंतरंगता थी और उससे वह शादी करना चाहती थी। 'एस. गोविंदराजू बनाम कर्नाटक राज्य', 2013 (10) एस.सी.ए.एल.ई. 454 के मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ ध्यान देने योग्य हैं:

> *"दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत जाँच के दौरान अभियुक्त के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने साथ जुड़ी आपराधिक परिस्थितियों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण दे और न्यायालय को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में भी इस तरह के स्पष्टीकरण पर ध्यान देना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हुई है या नहीं। जब अभियुक्त का ध्यान उन परिस्थितियों की ओर आकर्षित किया जाता है जो उसे अपराध करने के संबंध में प्रेरित करती हैं, और वह उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, या उसी के संबंध में गलत जवाब देता है, तो उक्त अधिनियम को परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक लापता कड़ी प्रदान करने के रूप में गिना जा सकता है।*

24. रोहतास कुमार बनाम हरियाणा राज्य : जे.टी. 2013 (8) एस.सी. 181 मामले में यह न्यायालय निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

निस्संदेह, अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना होगा। ***हालाँकि, कुछ परिस्थितियों में, अभियुक्त को उन दोषपूर्ण परिस्थितियों के लिए कुछ स्पष्टीकरण देना पड़ता है, जो उसके सामने सबूत के रूप में आई है। एक गलत स्पष्टीकरण*** *परिस्थितियों की श्रृंखला को* ***पूरा करने के लिए एक लापता कड़ी प्रदान करने के रूप में गिना जा सकता है।***

(जोर दिया गया)

25. अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक अपना मामला साबित किया और इसलिए साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 के प्रावधान लागू होते हैं। अपीलार्थी/अभियुक्त ने उसमें निहित उक्त अनुमान का खंडन करने का कोई भी प्रयास नहीं किया। इसके अलावा, मृतका शांति की मृत्यु अपीलार्थी के घर में हुई। उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि घटना के समय वह कहां था। ऐसी तथ्य-स्थिति में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों को भी लागू किया जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी/अभियुक्त को ऐसे तथ्यों के बारे में विशेष जानकारी थी, हालांकि वह कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा, इस प्रकार न्यायालय उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है।"

6. मृतका द्वारा दर्ज की गई मृत्युकालिक कथन किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है और इसकी सत्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। यह सच है

और स्वैच्छिक है और हितबद्ध पक्षकारगण द्वारा सिखाने का परिणाम नहीं है। मरते हुए व्यक्ति के शब्दों में बहुत गंभीरता और पवित्रता होती है। एक बार जब न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि घोषणा सत्य और स्वैच्छिक है, तो वह बिना पुष्टि के दोषसिद्धि का आधार बन सकता है।

7. अभि.सा.-9 (रेखा) उम्र 14 साल जो घटना के अंतिम पाँच दिनों से दंपत्ति घर में रह रही थी सबसे महत्वपूर्ण गवाह है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि शनिवार को पूर्वाहन लगभग 10.00 बजे अपीलार्थी-1 और अपीलार्थी-2 ने उसकी बहन को बुरी तरह से पीटा यह रविवार तक जारी रहा। इसके बाद उसकी बहन और अपीलार्थी-1 के बीच झगड़ा हो गया। उसे अपीलार्थी-1 ने 'रोटी' दी और उसे खाने के बाद वह नीचे आई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सीढ़ियों पर जलते और पड़े हुए पाया। दोनों आरोपी उसके पास खड़े थे। आरोपी गोपी और कोई परवीन उसकी बहन को अस्पताल ले गए। उसने घटना की जानकारी अपने माता-पिता को फोन पर दी। प्रति-परीक्षा में उसने बताया कि वह अपनी बहन की शारीरिक बीमारी के कारण उसकी मदद करने गई थी क्योंकि वह चलने में असमर्थ थी। इस बाल गवाह का अपीलार्थीगण को गलत तरीके से फंसाने का कोई गुप्त उद्देश्य नहीं था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि हेमलता ने खुद को आग लगा ली थी क्योंकि वह अपनी बीमारी से तंग आ चुकी थीं जिसने उसे अपंग बना दिया था। मृतका के पिता अभि.सा.-1 (बाबू लाल) ने भी अपीलार्थीगण पर दहेज की मांग

के कारण अपनी बेटी को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने क्रूरता का एक विशिष्ट उदाहरण दिया जब शादी में दिया गया बेड टूट गया था और उसे एक नया बेड लाने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अपनी अभ्यागमन के दौरान, हेमलता उन्हें कहती/बताती थी कि उनके पति और सास अधिक दहेज के लिए झगड़ा करते है और उन्हें पीटते हैं और स्कूटर एवं फ्रिज की मांग कर रहे हैं। प्रति-परीक्षा में, उन्होंने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि विवाह के समय अपीलार्थीगण द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। उसकी साली धनेश्वरी विवाह में मध्यस्थ थी जो अपीलार्थीगण के पड़ोस में रहती थी। मृतका के मामा अभि.सा.-5 (कन्हैया लाल) ने भी उसके बयान की पुष्टि की और कहा कि उससे मिलने के दौरान, हेमलता ने खुलासा किया था कि अपर्याप्त दहेज लाने के लिए उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा था। मृतका का भाई अभि.सा.-7 (हेमराज) ने बताया कि शादी के लगभग दो महीने बाद, उसने उसे बताया कि आरोपी उसे परेशान कर रहे हैं और वे एक दोपहिया स्कूटर की मांग कर रहे हैं। ले जाने के दौरान टूटे हुए पलंग और मेज को बदल दिया गया और नए दिए गए। उसने यह भी कहा कि अस्पताल में उसके साथ बातचीत के दौरान, उसने उसे बताया कि उसे पिछले तीन दिनों से पीटा जा रहा था। अभि.सा.-8 (कृष्णा) ने भी इसी तरह का अभिसाक्ष्य दिया। इन सभी गवाहों को झूठे बयान देने के पीछे कोई गुप्त उद्देश्य नहीं बताया गया। उनके साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई वैध कारण नहीं है क्योंकि वे सबसे स्वाभाविक गवाह हैं जिन पर मृतका विश्वास कर सकती है। गवाही की

सच्चाई का परीक्षण वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर किया जाना चाहिए और इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि ये गवाह मृतका के रिश्तेदार हैं। वैवाहिक विवाद में, बाहरी लोगों के आने और गवाही देने की अपेक्षा करना अनुचित होगा।

8. इस तर्क का अगला अंग कि धारा 304ख के तत्व मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के कारण क्रूरता या उत्पीड़न के अभाव में आकर्षित नहीं करते हैं, कोई बल नहीं है। 'हीरालाल और अन्य बनाम राज्य', ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 2865 में, उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी किया:

> *".....अभिव्यक्ति "ठीक पहले" बहुत प्रासंगिक है जहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख और भा.दं.सं. की धारा 304-ख लागू होती है। अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए बाध्य है कि घटना से तुरंत पहले क्रूरता या उत्पीड़न हुआ था और केवल उसी मामले में अनुमान लागु होता है। उस संबंध में साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 'ठीक पहले' एक सापेक्ष शब्द है और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है और इस बारे में कोई स्ट्रेट-जैकेट सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि घटना से पहले की अवधि क्या होगी। घटना से पहले किसी भी निश्चित अवधि का संकेत देना खतरनाक होगा। हालाँकि, यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि "ठीक पहले" अभिव्यक्ति का अर्थ आम तौर पर यह होगा कि संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न और प्रश्नगत मृत्यु के बीच का अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए। दहेज की माँग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच एक निकट और जीवंत संबंध का अस्तित्व होना चाहिए। यदि क्रूरता की कथित घटना का समय बहुत पहले*

का है और वह इतनी पुरानी हो चुकी है कि संबंधित महिला का मानसिक संतुलन बिगड़ने वाला नहीं है, तो इसका कोई महत्व नहीं होगा। ।"

9. इस मामले में, शादी केवल लगभग पाँच महीने तक चली थी और इस अवधि के दौरान वह लगभग चार महीने तक अपने दंपत्ति गृह (ससुराल) में रही। उसके माता-पिता से किसी भी समझौते की संभावना को खारिज करने के लिए शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस अधिकारियों के पास जाने की उम्मीद नहीं थी। शुरू में, विवाह को बचाने के लिए विवादों को सुलझा लेने और हल करने के प्रयास किए जाते हैं। मृतका ने स्पष्ट रूप से बताया कि अपीलार्थी के साथ रहने के दौरान दहेज की मांगों के कारण वे उन्हें परेशान करते थे। प्रश्नगत घटना से पहले भी, वे पिछले तीन दिनों से उसके साथ झगड़ रहे थे और इसने उसे आत्महत्या करके अपनी समस्याओं का अंत करने के लिए मजबूर कर दिया। दहेज की मांग और उसके परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु के संबंध में उत्पीड़न और क्रूरता के बीच अधिक निकट संबंध की कल्पना करना मुश्किल है। अपीलार्थीगण ने भा.दं.सं. की धारा 113ख के तहत कोई विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। बचाव पक्ष के गवाहों ने मृतका के आत्महत्या करने का कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया। आक्षेपित निर्णय साक्ष्य के उचित और निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित होता है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अभियोजन मामले के मूल को प्रभावित किए बिना मामूली विरोधाभासों, विसंगतियों, तुच्छ मामलों में सुधार को पूरी तरह से

साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। भा.दं.सं. की धारा 304ख के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा सात साल है और इसे संशोधित/बदला/कम नहीं किया जा सकता है।

10. अपीलों को अनुपयुक्त होने के कारण खारिज किया जाता है। अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी जाती है। अपीलार्थीगण को सजा की शेष अवधि पूरी करने के लिए 20 दिसंबर, 2013 को विचारण न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। विचारण न्यायालय को अभिलेख तुरंत वापस भेजा जाए।

(एस.पी.गर्ग)
न्यायाधीश

16 दिसंबर, 2013*/टी.आर.*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*